

Gem of आधुनिक समाचार 2026- श्रीमती पूनम सिंह

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) एजुकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने वर्ष 2005



भाविनी वेलफेयर सोसाइटी, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, सचिव - भाविनी संस्थान, अल्लापुर, प्रयागराज, अध्यक्ष - भाविनी स्वयं सहायता समूह, प्रयागराज। श्रीमती पूनम सिंह का जीवन संघर्ष, साहस और समाजसेवा की प्रेरणादायक मिसाल है। वर्ष 1995 में ब्रेन हेमरेज के कारण उन्हें लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया, किंतु उन्होंने कठिन परिस्थितियों के सामने हार न मानते हुए अपने जीवन को दिव्यांग बच्चों एवं जरूरतमंद महिलाओं की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। स्पेशल

में भाविनी वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत भाविनी डे-केयर की स्थापना की। यहाँ विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाता है। साथ ही भाविनी संस्थान के माध्यम से दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भरता एवं समाजसेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है।

वर्तमान की मांग है पर्यावरण संरक्षण - गुनेन्द्र प्रकाश

पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया ओपी यादव का 73वां जन्म दिन 30प्र0 के विभिन्न जनपदों में रोपित किए गए 73 पौधे

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। ओ.पी. यादव एसोसिएट्स सिविल कोर्ट



रायबरेली के तत्वाधान में बुधवार को सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीसी (फौ0) समाजवादी चिंतक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिवार के दीपक ओपी यादव का 73वां जन्म दिन पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर 30प्र0 के विभिन्न जनपदों में फलदार, सायादार एवं औषधी के 73 पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 30प्र0 न्यायिक सेवा संघ के महासचिव अपर जिला जज गुनेन्द्र प्रकाश ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की मांग है। पौधों में भी जान होती है और वह भी सांस लेते हैं। पेड़ों द्वारा छोड़ी जाने वाली आक्सीजन मानव जीवन के लिए वरदान है। सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश

कर रहे हैं। महामंत्री योगेन्द्र दीक्षित ने कहा कि ओपी यादव का जीवन संघर्षपूर्ण रहा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने पर 82 बार जेल गये। पूर्व महामंत्री सुनील सिंह ने कहा कि श्री यादव वकालत के साथ समाजसेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। प्रमुख व्यवसायी हरिहर सिंह ने कहा कि ओपी यादव की दादी इंदिरा यादव, बाबा सद्दू प्रसाद यादव, पिता बट्टी प्रसाद यादव 6 जनवरी 1921 को किसान आन्दोलन में जेल गये। विजय रस्तोगी ने कहा कि ओपी यादव की माँ उमराई यादव 12 वर्ष की आयु में वानर सेना में शामिल होकर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हुए जेल गयीं। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपक यादव ने कहा कि ओपी यादव को संघर्ष विरासत में मिला है।

एन.सी.एफ. की कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी सिंह ने की सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) नोएडा। सामाजिक कार्यवाई हो। पूरे प्रकरण की 'मजिस्ट्रियल जांच' कर रिपोर्ट



संगठन नौएडा सिटीजन फोरम (एन.सी.एफ.) की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट नौएडा से मिलकर युवा इंजीनियर आर्यन की दर्दनाक मृत्यु के मामले में ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगें इस प्रकार रही:- मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की जाए। दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कानूनी

सार्वजनिक की जाए। पीड़ित परिवार को रु50 लाख का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खुले नालों, टूटी स्लैबों और विद्युत व्यवस्था का 'विशेष सुरक्षा ऑडिट' कराया जाए। सिटी मजिस्ट्रेट ने विषय को ध्यानपूर्वक सुनकर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया।

देविका गोल्ड होम्स में नई एओए के चुनाव का रास्ता साफ, डिप्टी रजिस्ट्रार ने वर्तमान कार्यकारिणी को कालातीत घोषित किया

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) नोएडा। बुधवार को देविका गोल्ड होम्स अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए), जीएच-06सी, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज़ एवं चिट्स, गाजियाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में स्पष्ट

किया गया है कि वर्तमान कार्यकारिणी/एड-हॉक एओए का

निवासियों का मानना है कि नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव से

माध्यम से अब सोसायटी में सुशासन, पारदर्शिता और सभी



कार्यकाल समाप्त (कालातीत) हो चुका है। आदेश में यह भी कहा गया है कि समय पर चुनाव न कराए जाने के कारण अब सोसायटी में नई कार्यकारिणी के गठन हेतु वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक माह के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए सक्षम निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। यह आदेश उन सभी निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से एक वैधानिक, लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी एओए के गठन की मांग कर रहे थे।

सोसायटी में सुशासन, पारदर्शिता तथा सभी फ्लैट मालिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित होगी। प्रवीण सिंह, शिकायतकर्ता एवं सोसायटी निवासी ने कहा- 'यह आदेश केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि देविका गोल्ड होम्स के उन सभी निवासियों की लोकतांत्रिक जीत है जिन्होंने पिछले कई महीनों से एक वैधानिक, पारदर्शी और जवाबदेह एओए की मांग को शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से उठाया। हमें विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव के

निवासियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी। हम सभी निवासियों से अपील करते हैं कि वे चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और एक ऐसी एओए का चयन करें जो केवल निवासियों के हित में कार्य करे।' निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा विधिसम्मत एवं निष्पक्ष निर्णय लिए जाने पर आभार व्यक्त किया है तथा सभी फ्लैट मालिकों से आगामी चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर एक मजबूत, जवाबदेह एवं लोकतांत्रिक एओए के गठन में सहयोग करने की अपील की है।

उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन सम्पन्न

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) नोएडा। शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जनपद के

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्त हस्तांतरण में आ रही समस्याओं

पर ही आधारित हो। कृषकों की सहायता हेतु आयोजित इस किसान दिवस कार्यक्रम में कृषि



कृषकों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। उक्त क्रम में आज उप कृषि निदेशक कार्यालय, विकास भवन में उप कृषि निदेशक राजीव कुमार की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस में प्रगतिशील कृषकों ने सम्मिलित होते हुए अपनी समस्याओं को बैठक में रखा। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को फार्मर रजिस्ट्री, प्लैमिली आईडी एवं कृषि यंत्रीकरण से संबंधित विषयों पर जागरूक किया गया। साथ ही

के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि कई किसानों द्वारा सेल्फ रजिस्ट्रेशन के दौरान कृषि भूमि का विवरण सही प्रकार से दर्ज न किए जाने के कारण किस्त हस्तांतरण में कठिनाई आ रही है। ऐसे किसानों को जन सुविधा केंद्र के माध्यम से 'अपडेट मिसिंग फॉर्मेशन' विकल्प के अंतर्गत अपनी भूमि का विवरण संशोधित एवं अद्यतन कराने की जानकारी भी साझा की गई। साथ ही कार्यक्रम में इस विषय पर भी बल दिया गया कि किसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली खाद की मात्रा कृषक को उपलब्ध कराये गये सॉल्व हेल्थ कार्ड के निष्कर्षों

क्षेत्र से जुड़े विभागों के अधिकारी, जिसमें सिंचाई, ऊर्जा एवं कृषि उत्पादन शाखा से जुड़े विभाग जैसे कृषि, उद्यान, मत्स्य, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन आदि विभागों के अधिकारियों व एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सम्बन्धित समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अन्त में उप कृषि निदेशक द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी कृषकों, सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की गयी।



INDIAN SECURITY AND MANPOWER SERVICES




ADDRESS- Naini, Prayagraj U.P.-211008. PAN No. ABJPA1540R, Reg.No.03-0068604

Regd. Under Additional Director General of Police U.P. vide Reg. No. 2453 +91-7985619757, +91-7007472337

We Are Providing Security & Manpower Services in School/ University/ Institute/ Hospital/ Office Premises

INDIAN SECURITY AND MANPOWER SERVICES:-
takes great pleasure in Providing Security arrangement and Office Staff for your Organization premises. We have with us talented and well trained Disciplined persons, each having exposure to industrial/commercial security and intelligence knowledge in their field. Our personnel's are physically fit, courageous disciplined and well trained in their field. They are bold but polite, peace loving but not coward, friendly but shrews while duty, sharp in act but very claim and affable where presence of mind is lost by the common man, ailing but smelling the red hounds, work in the common climate but vigilant and faithfully to the organization. It is on account of the above trait that our services are engaged by reputed organization which consists of Schools, University, Banks, Government, Industrial Concern, Hotels, Hospitals, Educational Institutes, Housing Societies/Bungalows, Semi Government and Government Organization.

INDIAN SECURITY AND MANPOWER SERVICES is registered by:-
Additional Director General of Police, (Law & Order), Deputy Labour Commissioner, Employees Provident Fund Organization, Employees State Insurance Corporation, Goods & Services Tax, MSME Registration..(Govt. of India)

FOR JOB CONTACT:- 9569430885

INDIAN SECURITY AND MANPOWER SERVICES Manpower Category:-
Assignment Manager, Housekeeping Manager, Assignment Supervisor, Housekeeping Supervisor, Accountant, Driver, Computer Operator, Electrician, Data Entry operator, Carpenter, Clerk, Office Boy, M.T.S, Sweeper, Peon, Gardner, Computer Teacher, Agriculture Labour, TGT & PGT Teacher, Quality/Technical Manpower as per your requirement





जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आईजीआरएस की समीक्षा बैठक सम्पन्न, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सख्त निर्देश

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। बुधवार को फीडबैक वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्तर पर जनपद की बेहतर छवि स्थापित होगी तथा शासन स्तर पर जनपद की बेहतर छवि



जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समेकित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, विभागवार प्रगति, असंतुष्ट फीडबैक तथा खराब प्रदर्शन वाले विभागों की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने खराब प्रगति वाले विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आईजीआरएस का कोई भी प्रकरण डिफाल्टर न होने पाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने असंतुष्ट अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक निस्तारण करने के बजाय शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन मामलों में विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा शिकायतकर्ता संतुष्ट है, उन प्रकरणों में संतुष्टि का फीडबैक भी अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाए, जिससे जनपद की आईजीआरएस रैंकिंग में सुधार हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत के निस्तारण में पारदर्शिता एवं प्रमाणिकता बनाए रखते हुए स्थलीय निरीक्षण के दौरान जीपीएस लोकेशन युक्त फोटो पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। इससे शिकायतों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने अपने हाथों से खींचा रथ

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। प्रयागराज के

तिवारी ने बताया कि दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ



कीडगंज क्षेत्र में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, उत्साह और भक्तिभाव के साथ निकाली गई। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने रस्सी पकड़कर भगवान जगन्नाथ के रथ को अपने हाथों से खींचा। पूरे मार्ग में 'जय जगन्नाथ' के गगनभेदी जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जगह-जगह लोगों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा वर्षों से रथ यात्रा का स्वागत किया। रथ यात्रा में शामिल महेंद्र

दुःखद

जगन्नाथ रथयात्रा में भगदड़, तेज बारिश के बीच 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे

पुरी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान



भगदड़ मच गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों को घायल होने की खबर है। शाम 5 बजे पहाड़ी रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अचानक लोग रथों के पास जाने लगे। यात्रा रूट पर मौजूद

धक्का देने लगे, इससे भगदड़ मच गई। लोग एक-दूसरे पर गिरने लगे। पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है। इसके बाजूद 10 लाख से ज्यादा लोग यात्रा रूट पर मौजूद हैं। यात्रा मुख्य मंदिर से उकिमी दूर बने गुंडीचा मंदिर तक जाएगी।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की समीक्षा बैठक सम्पन्न, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से मिले आयुष्मान योजना का लाभ - डीएम आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने के लिए निर्देश

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। बुधवार को जिलाधिकारी सरनीत कौर

पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड वैकल एक

प्रगति अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष प्रयास किए जाएं तथा प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा कर



ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की वर्तमान स्थिति, विभागवार प्रगति तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के सभी पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड निर्धारित समय-सीमा वेक भीतर बनवाना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी

मध्य प्रदेश में सेन समाज का न्यायिक प्रतिनिधित्व: चुनौतियां, अवसर और भविष्य की रूपरेखा

और अनुभवी वकीलों की फौज नहीं होगी, तब तक इन बड़े मुद्दों को अदालतों में मजबूती से नहीं उठाया जा सकता। 4. असुरक्षा और अल्पविश्वास की कमी: किसी भी समाज का मनोबल इस बात से बढ़ता है कि शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में उसके प्रतिनिधि मौजूद हैं। जब सेन समाज का कोई व्यक्ति न्यायालय जाता है और वहां अपने समाज के चेहरों को नदारद पाता है, तो उसमें एक अनजाना डर और व्यवस्था के प्रति अविश्वास की



भावना पैदा होती है। अधिवक्ताओं की संख्या वृद्धि से समाज को होने वाले लाभ यदि सुनियोजित प्रयासों से जिला अदालतों और हाई कोर्ट में सेन समाज के वकीलों की संख्या में वृद्धि होती है, तो इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे: 1. सुलभ और त्वरित कानूनी सुरक्षा: समाज के प्रत्येक नागरिक को अपने आस-पास ही कानूनी सुरक्षा कवच मिल जाएगा। संकट के समय समाज के लोगों को यह भरोसा रहेगा कि उनकी पैरवी करने के लिए उनका अपना व्यक्ति मौजूद है, जो उनके हितों की रक्षा करेगा। 2. कानूनी साक्षरता और अधिकारों के प्रति चेतना: अधिक संख्या में वकील होने और किसी विश्वसनीय स्वजातीय मार्गदर्शक के अभाव में समाज के सीधे-साधे लोगों को अक्सर गलत सलाह दी जाती है। मुकदमों को जानबूझकर लंबा खींचा जाता है, जिससे समाज के लोगों का कीमती समय और गाढ़ी कमाई अदालत चक्करों में बर्बाद हो जाती है। 3. सामूहिक और नीतिगत पैरवी का अभाव: अक्सर समाज के जमीनी मुद्दों, जैसे- सामुदायिक अधिकारों का हनन, आरक्षण, सामाजिक प्रताड़ना या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही-पर जनहित याचिका (PIL) या मजबूत कानूनी पैरवी की आवश्यकता होती है। जब तक समाज के पास प्रखर

सामाजिक क्षेत्र में बदलाव, कानून की शिक्षा व्यक्ति को तार्किक, निरड और संवेदनशील बनाती है। विधि स्नातक युवा समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, रूढ़िवादिता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक वैचारिक और कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। वे समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों को सामाजिक और अनुसंधान के माध्यम से समाज की प्रतिष्ठा को समाज के भीतर और बाहर स्थापित करेंगे। 2. आर्थिक सुदृढ़ता के नए द्वार वकालत केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और कभी न मंदा का शिकार होने वाला व्यवसाय है। इसके अलावा, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए करियर के असीमित रास्ते खुलते हैं: न्यायिक सेवा: युवा 'सिविल जज' की परीक्षा उत्तीर्ण कर सीधे न्यायाधीश बन सकते हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र: बड़ी कंपनियों, बैंकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 'लीगल एडवाइजर' (कानूनी सलाहकार) के रूप में उच्च वेतन वाली नौकरियां पा सकते हैं। अकादमिक और अनुसंधान: विधि के क्षेत्र में प्रोफेसर या रिसर्चर बनकर सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। इससे समाज का आर्थिक स्तर सुधरेगा और गरीबी का कल दूटेगा। 3. राजनीतिक नेतृत्व का उदय भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो राष्ट्रपिता महात्मा

ममूरा गांव में भीषण आग, दो लोगों की मौत; विधायक पंकज सिंह ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) नोएडा। ममूरा गांव में आग लगने की घटना में दो लोगों की मौत हो जाने से क्षेत्र में शोक की लहर

हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं भवन में मौजूद अन्य सभी लोगों को



दौड़ गई। घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक हादसा है। दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी प्राप्त की। विधायक ने अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता शुरू किया। प्रशासन के अनुसार रेस्क्यू अभियान के दौरान आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। भवन में फंसे दो लोगों को गंभीर

सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद स्थानीय विधायक पंकज सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने आसपास के लोगों से भी घटना की जानकारी ली तथा प्रशासनिक अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी प्राप्त की। विधायक ने अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और घटना की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।

भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 27वें स्थापना दिवस एवं पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) भोपाल। भारतीय

राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का भोपाल (म.प्र.) में 15 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय अधिवेशन की मध्य प्रदेश के खैल-यूवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, डा. योगेंद्र कुमार मिश्र, पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डा. भगवान प्रसाद उपाध्याय, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मिश्र, महासचिव राकेश शर्मा, देश-दर्शन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप सिंह, वरिष्ठ साहित्यकार चित्रकूट के बब्बाजी, एवं जनपद कौशांबी से महेंद्र सेन एवं विभिन्न राज्यों के अनेक पदाधिकारी-पत्रकारगण। सम्मान एवं पुस्तक-विमोचन, के साथ संपन्न हुआ।

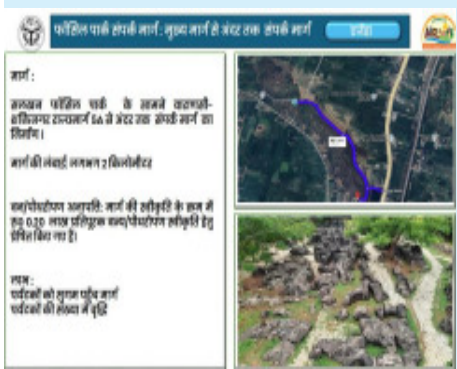
डीएम ने गुण्डा एक्ट के तहत 08 व्यक्तियों को 06 माह के लिए किया जिला बंदर

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। जिला मजिस्ट्रेट सरनीत कौर ब्रोका ने अपने न्यायालय में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-03 के अंतर्गत 08 व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बंदर की कार्रवाई की गई। न्यायालय द्वारा परित आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को 06 माह की अवधि के लिए जनपद रायबरेली की सीमा से बाहर निकालित किया गया है। जिला बंदर किए गए व्यक्तियों में (1) राजवीर उर्फ राज पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम निहुरी मजरा दीनशाहगौरा थाना गदागंज (2) अतिन्दर उर्फ ममा पुत्र स्वर्गीय जंगबहादुर सिंह निवासी ग्राम बरहा थाना खीरी (3) मो. कादर खान पुत्र शमशाद निवासी मुमुनी थाना सोलेन (4) संदीप कुमार शुक्ल पुत्र हरिकेश निवासी लेनापार मजरा डीघा थाना नसीराबाद (5) शैलेन्द्र सिंह पुत्र माताफेर निवासी ग्राम मोन थाना महाराजगंज (6) सतेन्द्र सेनकर उर्फ राजा सेनकर पुत्र रामपाल सेनकर निवासी नई बस्ती देवानन्दपुर थाना मिलहरिया (7) लवकुश मौर्य पुत्र शिवराम मौर्य निवासी ग्राम पूरे लाला प्रथम मजरा अशरफपुर थाना नसीराबाद (8) अमित शुक्ला पुत्र इन्द्रनारायण शुक्ला निवासी ग्राम कैदरी पोस्ट घरई थाना सोलेन जनपद रायबरेली शामिल हैं।

जनपद के विकास के खाके को मिली मंजूरी

डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, स्टेडियम, गोसंरक्षण, जल निकासी और पर्यटन विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को हरी झंडी

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) एवं संबंधित विभागों के सोनभद्र। जिला खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक



फाउंडेशन न्यास (डीएमएफ) की शासी परिषद की बैठक में

में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सड़क, सिंचाई, जल निकासी, महिला



खरवार, विधान परिषद सदस्य श्री विनीत सिंह, विधान परिषद सदस्य श्री आशुतोष सिन्हा, जिलाधिकारी श्री चंचित गौड़,

सहायक, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास तथा पशु संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए विकास

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, विद्यालयों का होगा कायाकल्प और युवाओं को मिलेगी नई सुविधाएं, सड़क, जल निकासी, सिंचाई, गोसंरक्षण और पर्यटन विकास को मिलेगी नई गति, ओबरा में खनन प्रशिक्षण विद्यालय की होगी स्थापना/ग्रामीण युवाओं के लिए आधुनिक मिनी स्टेडियम के निर्माण को भी दी गई स्वीकृति, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऑयलसीड प्रसंस्करण इकाई की होगी स्थापना, कृषक बन्धुओं के सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने हेतु चेकडैम का होगा निर्माण, जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों की उपस्थिति में लिए गए अहम निर्णय, मंगलेश्वर महादेव मार्ग एवं सलखन फॉसिल पार्क तक बेहतर संपर्क मार्ग विकसित करने व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण को भी नई गति देने की कार्ययोजना को मिली मंजूरी

मुख्य विकास अधिकारी जगजित अस्थो, अपर जिलाधिकारी श्री गंगीश कुमार शुक्ला, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री इन्द्रभान सिंह, ज्येष्ठ खान अधिकारी श्री कमल कश्यप सहित मा10 जनप्रतिनिधिगणों के प्रतिनिधि

का व्यापक खाका तैयार किया गया। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति की कार्ययोजना को मंजूरी देते हुए चिकित्सालयों एवं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया

गया। वहीं परिषदीय एवं माध्यमिक विद्यालयों में नए भवन, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, शौचालय, चहारदीवारी एवं अनुरक्षण कार्य कराए जाएंगे। ओबरा में खनन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना तथा ग्रामीण युवाओं के लिए आधुनिक मिनी स्टेडियम के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी। बैठक में ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया और संपर्क मार्गों के निर्माण, नगर क्षेत्रों में वैज्ञानिक ड्रेनेज प्रणाली विकसित कर जलभराव की समस्या को स्थायी समाधान, किसानों के लिए चेकडैम निर्माण, स्वयं सहायता



समूहों के माध्यम से ऑयलसीड प्रसंस्करण इकाई की स्थापना तथा बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए बुद्ध गोसंरक्षण केंद्र विकसित करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही मंगलेश्वर महादेव मार्ग एवं सलखन फॉसिल पार्क तक बेहतर संपर्क मार्ग विकसित करने और व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण को भी नई गति देने की कार्ययोजना को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी श्री चंचित गौड़ ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन न्यास से शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार, कृषि, पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देते हुए सोनभद्र के समग्र विकास की मजबूत आधारशिला रखी गयी है।

जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपद की सहकारी समितियों का किया गया औचक निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान खाद वितरण में शिथिलता पाये जाने पर 6 समितियों के सचिवों के वेतन भुगतान पर लगी रोक

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) भ्रमणशील रहकर समितियों पर बंद पाई गई, जहां किसानों को सोनभद्र। जिलाधिकारी चंचित उर्वरक उपलब्धता एवं वितरण डीएपी उर्वरक का वितरण नहीं



गौड़ के निर्देश पर जनपद में डीएपी, यूरिया उर्वरक वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रामगढ़



को लेकर प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत बुधवार को समस्त बी0पैक्स कोन में वितरण में अनियमितता पाये जाने पर

डीएपी उर्वरक वितरण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, समितियों के सचिवों का वेतन रोक, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए निर्देश

जनपद स्तरीय अधिकारियों, अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा सहकारी समितियों का व्यापक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सचिव के वेतन भुगतान पर रोक लगायी गयी इसी प्रकार से अरौली बी0 पैक्स, म्योरपुर बी0 पैक्स, चोपन बी0 पैक्स, कुरहर बी0 पैक्स, सहकारी समितियों के समयबद्ध रूप से उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि खरीफ सीजन में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बीजपुर पुलिस का वारंटियों पर शिकंजा, तीन अभियुक्त गिरफ्तार कर भेजे गए न्यायालय

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों को विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस



अधीक्षक (ऑपरेशन) श्री ऋषभ रुणवाल के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल निर्देशन तथा थानाध्यक्ष बीजपुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना बीजपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीन वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान थाना बीजपुर पर पंजीकृत मु0नं0-2296/2009, धारा 419, 420 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त रामजनम पुत्र सन्त लाल एवं तेजबली पुत्र रामरतन जायसवाल, निवासीगण ग्राम पिण्डारी, थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र को दिनांक 16.07.2026 को प्रातः लगभग 08:10 बजे उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में थाना बीजपुर पर पंजीकृत मु0नं0-3208/2019, धारा 323, 504, 506 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त बेचनराम पुत्र स्वर्गीय रामदास उर्फ दासाराम, निवासी ग्राम कखा बीजपुर, थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र को दिनांक 16.07.2026 को प्रातः लगभग 08:56 बजे उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। पूर्ण कर तीनों वारंटी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण- 1. रामजनम पुत्र सन्त लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम पिण्डारी, थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 2. तेजबली पुत्र रामरतन जायसवाल, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी ग्राम पिण्डारी, थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 3. बेचनराम पुत्र स्वर्गीय रामदास उर्फ दासाराम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम कखा बीजपुर, थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 4. हेड कांस्टेबल भानु प्रताप यादव थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 5. आरक्षी प्रकाश कुमार थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 6. आरक्षी अनिल कुमार थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 7. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 8. हेड कांस्टेबल भानु प्रताप यादव थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 9. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 10. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 11. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 12. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 13. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 14. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 15. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 16. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 17. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 18. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 19. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 20. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 21. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 22. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 23. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 24. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 25. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 26. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 27. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 28. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 29. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 30. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 31. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 32. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 33. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 34. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 35. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 36. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 37. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 38. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 39. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 40. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 41. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 42. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 43. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 44. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 45. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 46. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 47. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 48. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 49. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 50. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 51. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 52. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 53. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 54. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 55. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 56. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 57. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 58. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 59. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 60. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 61. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 62. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 63. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 64. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 65. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 66. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 67. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 68. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 69. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 70. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 71. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 72. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 73. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 74. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 75. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 76. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 77. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 78. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 79. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 80. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 81. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 82. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 83. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 84. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 85. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 86. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 87. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 88. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 89. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 90. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 91. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 92. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 93. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 94. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 95. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 96. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 97. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 98. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 99. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र। 100. आरक्षी देवकरन थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र।



NAINI INDUSTRIAL TRAINING CENTRE

(Govt. Affiliated, Star Graded, Record Holder, ISO Certified Training Centre)

सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी एण्ड इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी

फायर सेफ्टी पर जिसकी कमाण्ड, उसकी ही है ग्लोबल डिमाण्ड

कोर्स के बाद सेफ्टी सुपरवाइजर, फायर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आदि विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिल जाती है। रिलीफ एजेन्सी N.G.O., डिफेन्स सर्विसेज फायर सर्विस आर्डिनेन्स फैक्ट्री, महानगर पालिका, नगर निगम, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, माइनिंग इण्डस्ट्रीज, पेट्रोलियम कम्पनी, फूड इण्डस्ट्रीज, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल मिल, टावर कम्पनी, इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी, कोयले की खदानों एवं जहाजों आदि क्षेत्रों में फायर सेफ्टी के जानकारों को बहुत अधिक मौका मिलता है

नोट: फायर सेफ्टी कोर्स करें और देश-विदेश, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी पायें।

Visit us at www.nainiiti.com Call: 9415608710, 7459860480



मानसून में बढ़ते फूड पॉइजनिंग के केस, ये लक्षण इग्नोर न करें, बचाव के लिए सावधानियां, बता रहे हैं डॉक्टर

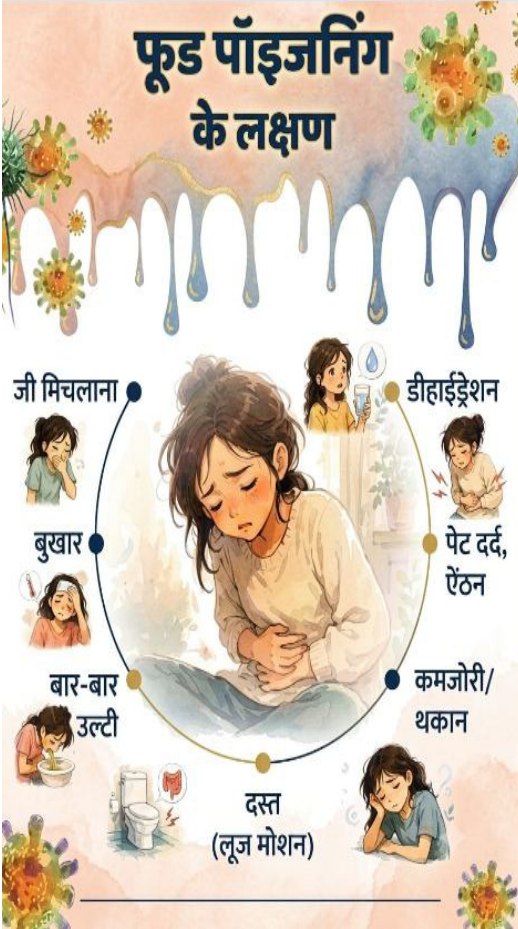
जयपुर। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है। इससे खाने-पीने की चीजों में बैक्टीरिया और वायरस जल्दी पनपते हैं। यही वजह है कि इस मौसम में फूड पॉइजनिंग ज्यादा

वायरस, पैरासाइट या उनके टोक्सिन्स के कारण होता है। सवाल- फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? जवाब- फूड पॉइजनिंग मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी से होती है। दूषित पानी पीने से।

पॉइजनिंग की शुरुआत में उल्टी और दस्त जैसे लक्षण दिखते हैं। समय पर ध्यान न देने से लक्षण गंभीर हो सकते हैं। जी मिचलाना, बुखार, बार-बार उल्टी दस्त (लूज मोशन) डीहाइड्रेशन, पेट दर्द,

सब्जियां। सवाल- अगर बाहर खाना मजबूरी हो तो किन बातों का ध्यान रखें? जवाब- बाहर ऐसी जगह खाएं, जहां साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता हो। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखें- बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह न जाएं। खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं।

बोतलबंद या पैकड पानी ही पिएं। ताजा और गरम खाना ही ऑर्डर करें। खुले में रखा या पहले से बना खाना न लें। कच्चा सलाद, कटे फल और चटनी न लें। खाने का स्वाद अजीब हो तो तुरंत छोड़ दें। बर्फ वाले ड्रिंक्स न पिएं। कच्चा या अधपका नॉनवेज न खाएं। एक्सपायरी डेट देखकर ही पैकड फूड खरीदें। सवाल- मानसून में घर में खाना स्टोर करते समय क्या सावधानियां बरतें? जवाब- खाना स्टोर करते समय बरतें ये सावधानियां- पका हुआ खाना ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में रखें। खाने को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। कच्चा और पका खाना अलग-अलग रखें। फ्रिज का तापमान सही रखें (लगभग 4 डिग्री)। बासी या स्मेल वाला खाना तुरंत फेंक दें। फ्रिज और किचन की नियमित सफाई करें। बार-बार गर्म करके खाना स्टोर न करें। बारिश में फूड पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए उल्टी, दस्त या बुखार को नजरअंदाज न करें। साफ पानी पिएं, ताजा खाना खाएं। लक्षण बढ़ें या 24-48 घंटे में राहत न मिले तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। सवाल- अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या करें? जवाब- ऐसी स्थिति में शरीर को हाइड्रेट रखना और डाइजैस्टिव सिस्टम को आराम देना जरूरी है। हल्के लक्षणों में घर पर देखभाल से सुधार हो सकता है, लेकिन समस्या बढ़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। फूड पॉइजनिंग में इन बातों का ध्यान रखें- ज्यादा से ज्यादा पानी, ओआरएस या नारियल पानी लें। हल्का और सुपाच्य खाना (खिचड़ी, दही, सूप) खाएं।



होती है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) के मुताबिक, मानसून के दौरान ई.कोली और

स्ट्रीट फूड खाने से। खुले में रखा फूड खाने से। बासी खाना खाने से। अधपका मीट, अंडा खाने से। बिना धुले फल-सब्जियां खाने से। बिना हाथ धुले खाना

खाना खाएं। बचा खाना तुरंत फ्रिज में रखें। उबला/फिल्टर्ड पानी पिएं। फल-सब्जियां धोकर खाएं। खाने से पहले हाथ धोएं। खाना पकाने से पहले हाथ धोएं। कच्चा-



सल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। बढ़ी हुई नमी, जलभराव और दूषित भोजन-पानी इसके मुख्य कारण हैं। इस कारण फूड पॉइजनिंग, डायरिया और हैजा के मामले बढ़ जाते हैं। हालांकि कुछ बुनियादी सावधानियां अपनाकर इन बीमारियों के रिस्क से बचा जा सकता है। इसलिए आज 'जरूरत की खबर' में हम फूड पॉइजनिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि- फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हैं? बारिश में फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए क्या करें? विषय को समझेंगे एक्सपर्ट- डॉ. वृज क्लृप्त शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर जी के साथ सवाल जवाब के माध्यम से। सवाल- फूड पॉइजनिंग क्या है? जवाब- फूड पॉइजनिंग दूषित भोजन-पानी से होने वाला संक्रमण है। यह बैक्टीरिया,

पकाने से। गलत फूड स्टोरेज से। एक्सपायर्ड फूड खाने से। बिना हाथ धुले खाने से। कच्चा-पका खाना साथ रखने से। सवाल- मानसून में फूड पॉइजनिंग के केसेज क्यों बढ़ जाते हैं? जवाब- इसे पॉइंटर्स से समझिए- मानसून में वातावरण में नमी बढ़ जाती है। यह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। इस कारण खाना जल्दी खराब होता है। इससे खाने से फूड पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ता है। बारिश के दौरान पानी भी जल्दी दूषित होता है। सब्जियां, फल, स्ट्रीट फूड और खुले में रखा खाना गंदे पानी या मक्खियों के संपर्क में आता है। इससे संक्रमण का रिस्क बढ़ जाता है। मानसून में डाइजैस्टिव सिस्टम भी थोड़ा स्लो होता है। इससे शरीर संक्रमण से मजबूती के साथ नहीं लड़ पाता है। सवाल- फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हैं? जवाब- फूड

पका खाना अलग रखें। लंबे समय से कटे फल न खाएं। फास्ट फूड, जंक फूड खाने से फूड न खाएं। पहले गर्म करें। स्ट्रीट फूड खुले में बन रहा जूस न पिएं। सवाल- बारिश में फूड पॉइजनिंग से बचाव के लिए खानपान में क्या बदलाव करें? जवाब- सही खानपान ही फूड पॉइजनिंग से बचाव का आसान तरीका है। नीचे देखें कि इस मौसम में क्या खाएं और क्या न खाएं। क्या खाएं- ताजा, गरम खाना और अच्छी तरह पका हुआ खाना। घर का बना खाना। दाल, खिचड़ी, सूप जैसी हल्की डाइट। मीसमो (अच्छे की थोकर)। क्या न खाएं- खुले में रखा खाना। स्ट्रीट फूड। बासी खाना। खुले में रखे कटे हुए फल। अधपका मीट, अंडा या सीफूड। ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना। पैकड फूड। बिना धुले फल-

शरीर को पर्याप्त आराम दें। खुद से एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं न लें। सवाल- फूड पॉइजनिंग का इलाज कैसे होता है? जवाब- इसका इलाज लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है, जैसेकि- डॉक्टर शरीर में पानी की कमी पूरी करने के लिए ओआरएस देते हैं। उल्टी और दस्त कंट्रोल करने के लिए दवाएं देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देते हैं। ज्यादा कमजोरी या डीहाइड्रेशन में ड्रिप (आईवी फ्लूइड) लगाया जा सकता है। सवाल- डॉक्टर को कब दिखाएं? जवाब- फूड पॉइजनिंग के इन लक्षणों को इग्नोर न करें, क्योंकि ये गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। इन स्थितियों में डॉक्टर को जरूर दिखाएं- बार-बार उल्टी हो। दस्त के साथ ब्लूडिंग हो। तेज बुखार (103°F से ज्यादा) हो। डीहाइड्रेशन (चक्कर, सूखा मुंह, कम पेशाब) हो।

वनडे और टी-20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होंगे, वनडे में सेमीफाइनलिस्ट सुपर-7 से, टी-20 में सुपर-10 से तय होंगे और भी कुछ नियम..

स्पोर्ट्स डेस्क। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप और 2028 का टी-20 वर्ल्डकप नए फॉर्मेट में होगा। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों के साथ नया

ग्री-स्टेज फॉर्मेट लागू होगा, जिसमें सेमीफाइनलिस्ट सुपर-7 राउंड से चुने जाएंगे। अब तक यह सुपर-6 से चुने जाते थे। वहीं, टी-20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 की जगह सुपर-10 स्टेज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दो नए एलिमिनेटर मुकाबले भी जोड़े गए हैं। आईसीसी ने बुधवार को नए फॉर्मेट में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 2028 टी-20 वर्ल्ड कप के लिए नया क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है। इनका एलान एडिनबर्ग में हुई आईसीसी की सालाना बैठक (एजीएम) के बाद किया गया। वनडे वर्ल्डकप में 14 टीमों की हिस्सा लेंगी- वनडे वर्ल्ड

कप में 14 टीमों की खेलेगी, लेकिन फॉर्मेट को ग्री-स्टेज में बदल दिया गया है। नए फॉर्मेट में सबसे पहले सुपर सीरीज खेली जाएगी। इसमें

तीसरे राउंड यानी सुपर-7 में पहुंचेगी। सुपर-7 में सभी सात टीमों में राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में कुल 21 मैच खेलेगी। इसके

बाद टॉप-4 टीमों में सेमीफाइनल (1 बनाम 4 और 2 बनाम 3) में पहुंचेगी। इनकी विजेता टीमों फाइनल खेलेगी। 2027 वनडे वर्ल्ड कप में ऐसे तय होंगे 14 टीमों- 2027 वनडे वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमों खेलेगी। इनमें दो मेजबान (साथ

अफ्रीका, जिम्बाब्वे), रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वालिफाई करने वाली टॉप-8 टीमों और वर्ल्ड कप क्वालिफायर से आने वाली टीमों शामिल होंगी। तीसरे होस्ट नामीबिया को भी क्वालिफायर खेलना होगा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इन 14 टीमों में सबसे निचली रैंक वाली तीन टीमों (12वीं,

13वीं और 14वीं) राउंड-1 खेलेगी, जिसमें सिर्फ एक टीम अगले दौर में पहुंचेगी। इसके बाद बाकी 11 टीमों के साथ मिलकर 12 टीमों दो ग्रुप (6-6) में खेलेगी। दोनों ग्रुप से टॉप-3 और चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों में से बेहतर एक टीम सुपर-7 में पहुंचेगी। सुपर-7 की सातों टीमों राउंड-रॉबिन मुकाबले खेलेगी, जहां से टॉप-4 टीमों सेमीफाइनल और फिर फाइनल के जरिए चैंपियन तय करेंगी। पुराने फॉर्मेट में दो ग्रुप और सुपर सिक्स स्टेज होती थी- पुराने फॉर्मेट में 7-7 टीमों के दो ग्रुप होते थे, दोनों ग्रुप की टॉप-3 टीमों सुपर सिक्स में पहुंचती थीं। सुपर सिक्स में 3-3 टीमों के दो ग्रुप बनते थे, जहां कुल 9 मैच खेले जाते थे। इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमों सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पहुंचती थीं।

बेटा बड़ा हो रहा है, डरती हूं, कहीं गलत संगत में न पड़ जाए, उसे सही-गलत में फर्क करना, अच्छे दोस्त चुनना कैसे सिखाएं

मुंबई। सवाल- मैं लखनऊ से हूं। मेरा बेटा 12 साल का है। हाल ही में उसका स्कूल बदला है। उसने वहां कुछ नए दोस्त बनाए हैं और अब उन्हीं के साथ ज्यादा समय बिताता है। एक मां होने के नाते मुझे खुशी है

डाल सकते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का लक्ष्य बच्चे के लिए अच्छा दोस्त चुनने की बजाय अपने बच्चे को इतना समझदार बनाना होना चाहिए कि वह खुद अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दोस्तों

“क्या उसके साथ रहने पर तुम्हें अच्छा महसूस होता है?” जब बच्चा इन सवालों पर सोचता है, तो वह धीरे-धीरे दोस्ती की क्वालिटी को समझना शुरू करता है। हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि एक अच्छे दोस्त की

खुलकर बातें करता है। बच्चे की जासूसी न करें-कई बार पेरेंट्स बच्चे के दोस्तों को जानने-समझने के लिए जासूसी करते हैं या हमेशा पूछताछ करते रहते हैं। ये हेलदी तरीका नहीं है। बच्चे के दोस्त कैसे हैं,

उसकी संगत कैसी है, इसे परखने के लिए कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसेकि-दोस्तों को घर बुलाएं। उनके साथ खेलें, बातें करें। खुलकर बातचीत करें। उनका बैकग्राउंड समझें। उनके पेरेंट्स के बारे में जानें। बिना जजमेंट के उन्हें सुनें। आप भी ध्यान दें, मदद उनके दोस्त बनें। का हाथ बढ़ाएं स्कूल एक्टिविटीज में रुचि लें। कैसे समझें, बच्चा बुरी संगत में है? टीनएज में बच्चे दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर नए दोस्त बनाने के बाद बच्चे के व्यवहार, आदतों या सोच में नकारात्मक बदलाव दिखे तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बच्चे की संगत ठीक नहीं है। गलत संगत के वर्निंग साइन्स- झूठ बोलना। बातें छिपाना। पढ़ाई में रुचि कम होना। जिम्मेदारियों से बचना। घर के नियम तोड़ना। गलतियां न मानना। गाली- गलौज करना। दूसरों को परेशान आक्रामक व्यवहार करना। अगर बच्चे में ये संकेत दिखें तो सतर्क हो जाएं। डांटने की बजाय बच्चे से खुलकर बात करें। संगत खराब हो तो क्या करें? पहले स्थिति को समझने की कोशिश करें। आपका उद्देश्य दोस्ती खत्म कराना नहीं, बल्कि बच्चे को सही-गलत समझने में मदद कराना होना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं- ध्यान से बातचीत करें। सही-गलत का फर्क समझाएं। घर में भरोसे का माहौल बनाएं। बच्चे की बात ध्यान से सुनें। पीयर प्रेशर पर चर्चा करें। खुद अच्छे रिश्तों के उदाहरण दें। दोस्तों के बारे में बात करें। बच्चे को निर्णय लेना सिखाएं। जरूरत से ज्यादा कंट्रोल न करें। स्कूल काउंसलर की मदद लें। पेरेंट्स की कॉमन गलतियां- कई बार माता-पिता बच्चे के दोस्तों को बिना जाने-समझे जज कर लेते हैं। इससे बच्चा अपनी सोशल लाइफ छिपाने लगता है और पेरेंट्स से दूर होने लगता है। इसलिए इन गलतियों से बचें-हर दोस्त को बुरा मान लेना। दोस्ती पर पूरी रोक लगा देना। बच्चे की बात सुने बिना फैसला करना। दूसरों बच्चों से तुलना करना। दोस्तों का अपमान करना। हर समय निगरानी रखना। बिना वजह पड़ने पर आपके साथ बच्चे को सही-गलत समझना। दोस्तों के शर्मिंदा करना। अपनी पसंद बच्चे पर थोपना। अंत में यही कहनी कि दोस्ती बच्चे की पर्सनैलिटी को शोप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए माता-पिता का काम हर दोस्त को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि बच्चे को अच्छे और बुरे प्रभाव में फर्क करना सिखाना है। जब घर में भरोसे और बातचीत का माहौल होता है, तो कच्चा किसी भी परेशानी या गलत प्रभाव के बारे में खुलकर बात करने में सहज महसूस करता है। यही भरोसा उसे सही दोस्त चुनने और जीवन में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है।



कि वह घुल-मिल रहा है, लेकिन यह चिंता भी रहती है कि कहीं वह गलत संगत में न पड़ जाए। मैं हर दोस्त की जांच-पड़ताल भी नहीं करना चाहती। मेरा सवाल ये है कि बच्चों को कैसे समझाएं कि कौन-सी दोस्ती उनके लिए अच्छी है? किस तरह के लोगों से दूरी बनाना बेहतर है? विषय को समझेंगे एक्सपर्ट- रिद्धि दोषी पटेल, चाइल्ड एंड पेरेंटिंग साइकोलॉजिस्ट, बच्चों के जीवन में दोस्ती का प्रभाव- जब बच्चा छोटा होता है, तब उसके लिए माता-पिता सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वह टीनएज के करीब पहुंचता है, उसकी जिंदगी में दोस्तों की भूमिका बढ़ने लगती है। इस उम्र में बच्चा चाहता है कि- उसे स्वीकार किया जाए। वह किसी ग्रुप का हिस्सा बने। लोग उसे पसंद करें। उसके डेर सारे दोस्त बनें। इसी वजह से कई बार बच्चे दोस्तों की आदतें, भाषा, व्यवहार, रुचियों और शौक को अपनाते लगते हैं। यह विकास का सामान्य हिस्सा है। लेकिन समस्या तब होती है, जब बच्चा दोस्ती में बने रहने के लिए अपनी समझ और मूल्यों को नजरअंदाज करने लगता है। अच्चा दोस्त कैसा होता है? अक्सर माता-पिता बच्चों को यह बताते हैं कि किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह बताना है कि अच्चा दोस्ती कैसी होनी चाहिए? “तुम लोग साथ में क्या करते हो?” जब बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी दोस्ती को समझना चाहते हैं, तब वह

की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अच्चे दोस्त बच्चों में आत्मविश्वास, सहयोग और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। जबकि गलत संगत पर्सनैलिटी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों के जीवन में दोस्ती का प्रभाव- जब बच्चा छोटा होता है, तब उसके लिए माता-पिता सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वह टीनएज के करीब पहुंचता है, उसकी जिंदगी में दोस्तों की भूमिका बढ़ने लगती है। इस उम्र में बच्चा चाहता है कि- उसे स्वीकार किया जाए। वह किसी ग्रुप का हिस्सा बने। लोग उसे पसंद करें। उसके डेर सारे दोस्त बनें। इसी वजह से कई बार बच्चे दोस्तों की आदतें, भाषा, व्यवहार, रुचियों और शौक को अपनाते लगते हैं। यह विकास का सामान्य हिस्सा है। लेकिन समस्या तब होती है, जब बच्चा दोस्ती में बने रहने के लिए अपनी समझ और मूल्यों को नजरअंदाज करने लगता है। अच्चा दोस्त कैसा होता है? अक्सर माता-पिता बच्चों को यह बताते हैं कि किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह बताना है कि अच्चा दोस्ती कैसी होनी चाहिए? “तुम लोग साथ में क्या करते हो?” जब बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी दोस्ती को समझना चाहते हैं, तब वह

पहचान क्या होती है। अच्चे दोस्त की पहचान-सम्मान करता हो। भरोसेमंद हो। सच बोलता हो। मदद करने वाला हो। गलत कामों से बचाए। मजाक न उड़ाए। भावनाओं की कद्र करे। आपकी सफलता से खुश हो। मुश्किल समय में साथ दे। सकारात्मक सोच रखता हो। दोस्ती में सम्मान और भरोसा जरूरी-कई बच्चे सोचते हैं कि जो उनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, वही उनका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन असल में अच्छी दोस्ती का आधार सम्मान और भरोसा होता है। उसे बताएं कि एक अच्छा दोस्त- ‘आपका मजाक नहीं उड़ाता।’ ‘आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाता।’ ‘आपकी सफलता से जलता नहीं है।’ ‘गलत काम के लिए दबाव नहीं डालता है।’ ‘जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ा रहता है।’ साथ ही बच्चे को समझाएं कि दोस्ती में डर, दबाव या अपमान की कोई जगह नहीं होती है। बच्चे के दोस्तों में दिखाएं रुचि- बहुत से माता-पिता बच्चे के दोस्तों में रुचि नहीं दिखाते, जबकि इससे बच्चे को इमोशनल सपोर्ट मिलता है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं- ‘आज स्कूल में किसके साथ बैठे थे?’ ‘तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगता है?’ ‘तुम लोग साथ में क्या करते हो?’ जब बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी दोस्ती को समझना चाहते हैं, तब वह

दुनिया के शहर मिलकर भी क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं

जलवायु परिवर्तन वे खिलाफ पूरी दुनिया ही एक लड़ाई लड़ रही है। इस संघर्ष में लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं की कोई कमी



नहीं रही हैं। लेकिन अंततः लोग इस दिशा में हुई प्रगति का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वे अपने दैनिक जीवन में क्या अनुभव करते हैं। और जलवायु कार्रवाई का प्रभाव दुनिया के शहरों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। शहरों में यह समझ अब बनने लगी है कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने और जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ाने वाले उपाय लोगों के दैनिक जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। एनर्जी-इफिशिएंट घर बिजली के बिल को कम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आयातित-ईंधनों पर निर्भरता और तेल-गैस की कीमतों में उछाल से पैदा होने वाली मुश्किलों को कम करती है। बेहतर सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को आने-जाने के लिए अधिक किफायती और स्वस्थ विकल्प उपलब्ध कराता है। पेड़ और ग्रीन बेल्ट हवा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, इलाकों को ठंडा रखते हैं और शहरों को रहने के लिए अधिक सुखद बनाते हैं। लेकिन जलवायु कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही नहीं है। यह लोगों को गर्म होती पृथ्वी के पहले से स्पष्ट हो चुके प्रभावों से सुरक्षित रखने का भी

लगातार अधिक तीव्र हो रही हैं। शहर और उनके निवासी इन चुनौतियों का सबसे पहले सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए एडारेशन के उपायों को भी आगे बढ़ाना होगा। दुनिया भर में स्थानीय नेतृत्व स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और सार्वजनिक स्थलों को अत्यधिक गर्मी तथा अन्य जलवायु जोखिमों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनुकूल बनाने के प्रयास कर रहा है। छायादार व्यवस्थाएं, ग्रीन रूफ और प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम्स बढ़ते तापमान के प्रति शहरों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसका सबसे अधिक लाभ बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील समूहों को मिलता है। आज दुनिया के कई बड़े शहरों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटा है, जबकि उनकी आबादी लगातार बढ़ती रही है। इसके अलावा, तमाम तरह के शहर मिलकर उस प्रगति को और तेज करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो उन्होंने अलग-अलग स्तर पर हासिल की हैं। पिछले एक दशक में ग्लोबल कोवेनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी (जीसीओएम) 150 देशों के 14,000 से अधिक शहरों और स्थानीय सरकारों के गठबंधन के रूप में विकसित हुआ

भारत के भी 29 शहर शामिल हैं और सबसे नया सदस्य तिरुवनंतपुरम है। इसके अनेक सदस्य शहरों ने अपनी सरकारों की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी



जलवायु लक्ष्य अपनाए हैं और उन्हें अधिक तेजी से हासिल करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। फिर भी, यदि उन्हें अधिक सहयोग मिले तो वे और तेजी से तथा अधिक व्यापक स्तर पर काम कर सकते हैं। उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता और फंडिंग तक पहुंच करी तत्काल आवश्यकता है। अनेक स्थानीय निकायों के पास अब भी इतने

संसाधन नहीं हैं कि वे जलवायु परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन कर सकें। साझेदारी से इन जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सिटी क्लाइमेट फाइनैस गैप फंड-जिसे जीसीओएम और विश्व बैंक का समर्थन प्राप्त है- पहले ही ऐसी परियोजनाएं विकसित करने में शहरों को सहायता दे रहा है, जो निवेश को आकर्षित कर सकें और आबादी को लाभ पहुंचा सकें। पिछले कुछ वर्षों में इसने 1,400 से अधिक शहरों को जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने में सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय सरकारें अब जलवायु परिवर्तन से निपटने में शहरों की क्षमता को तेजी से स्वीकार कर रही हैं। लेकिन इसे वेगवल शुरुआत माना जाना चाहिए। सबसे सफल जलवायु-नीतियां वही होती हैं, जिनका असर लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में देख और महसूस कर सकें, यानी स्वच्छ हवा, अधिक सुरक्षित सड़कें, बिजली का कम बिल, अधिक स्वस्थ घर और एक्स्ट्रीम-

किसी दिन ‘कोडी’ कई बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होगा

अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है,

कुडिया और बेन गॉर्टजेल के दिमाग में आया था। ‘कोडी’ का मुस्कराता हुआ चेहरा है,

जुड़ने और कम अकेलापन महसूस करने में मदद करेगा। लेकिन को-फाउंडर्स का मानना

होगी कि आने वाले वर्षों में बच्चों से दूर रहने वाले पैरेंट्स या निःसंतान लोगों को ‘कोडी’ जैसे



लेकिन आप किसी ओल्ड-एज होम में भी नहीं जाना चाहते हैं, और उसके बजाय अपने ही घर में रहना चाहते हैं तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया में हुआ अध्ययन कहता है कि 95इ से अधिक बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक फायदों के चलते हमेशा उसी घर में उम्र बिताना पसंद करते हैं, जहां दशकों से रहते आए हैं। दक्षिण कोरिया सबसे तेजी से बुजुर्ग होती आबादी वाले देशों में एक है और पिछले साल वह ‘सुपर-एज सोसाइटी’ बन गया। लेकिन उन लोगों का क्या होगा, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में या विदेश चले गए हैं या शादी के बाद आपके घर से चले गए? उनकी जगह ‘कोडी’ लेगा। सोच रहे हैं कि ‘कोडी’ कौन है? तो आगे पढ़िए। हम इंसान जहां चंद महीने में बच्चों को जन्म दे सकते हैं, जो बड़े होकर हमारी देखभाल करते हैं, वहीं ‘कोडी’ के पैरेंट्स को उसे दुनिया के सामने लाने में लगभग तीन साल लग गए। इसानी जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए ‘कोडी’ का विचार क्रिस

हालांकि उसकी चमकीली भूरी आंखें आपको असहज कर सकती हैं। उसका तीन फीट का फ्रेम, शरारती मुस्कान के साथ चेहरे के दोस्ताना भाव उसे सहज बनाते हैं। हां, वह अमेरिका के सिएटल की कंपनी ‘माइंड यिल्ड्रून’ का एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। 11 जून को उसने अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू दिया। उससे पूछा गया कि उसके सामने क्या है। बच्चों जैसी आवाज में उसने तुरंत कहा कि ‘स्त्रीनों वाला एक वर्कप्लेस, जहां कुछ नोट्स और रोजमर्रा की चीजें हैं। यह किसी क्लासिक लैब जैसा सेटअप दिखता है, जो विचारों को जीवन में उतारने की अच्छी जगह जैसा लगता है।’ हालांकि आज वह चाय का कप भी नहीं उठा सकता, लेकिन वह आश्चस्त है कि अगले 10 साल में वह सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ कर पाएगा। वह कहता है, ‘शायद तब तक मैं एलेक्टा के दरवाजे भी खोल सकूंगा।’ उसके को-फाउंडर्स को भी भरोसा है कि यह रोबोट स्कूलों, अस्पतालों, होटलों और घरों का हिस्सा बनेगा। लोगों को सीखने,

है कि उससे पहले ‘कोडी’ को कई बाधाएं पार करनी होंगी। ‘माइंड यिल्ड्रून’ कंपनी ने इसके विकास के अगले चरण के लिए क्राउडफंडिंग शुरू कर दी है। उसे उम्मीद है कि एक बार लॉन्च होने पर वह इसे इतना सस्ता बना देगी कि अकेले रहने वाले वयस्क इसे खरीद सकें। जब भी ऐसी नई तकनीक बाजार में आती है तो शुरू में वह बेहद अमीर लोगों का खिलौना बन जाती है। आज कुछ होम-रोबोट 20 हजार डॉलर में बिक रहे हैं, लेकिन को-फाउंडर्स चाहते हैं कि ‘कोडी’ की कीमत 10 हजार डॉलर हो। दोनों को भरोसा है कि वे ‘कोडी’ के ऐसे इस्तेमाल के बेहद करीब हैं, जहां वह बुजुर्गों की देखभाल कर सके और उनके अकेलेपन से लड़ सके। होटलों और आर्ट गैलरियों में इसकी पायलट स्टडी चल रही है, ताकि इसके विकास के लिए जरूरी डेटा जुटाए जा सकें। फिर 2027 में ‘कोडी’ का दूसरा संस्करण तैयार किया जाएगा। ऐसे विश्व में, जहां ह्यूमनॉइड मशीनें दुनिया की समझ से भी तेज गति से बढ़ रही हैं, यह हैरानी की बात नहीं

रोबोट उपहार में दिए जाने लगे। ‘कोडी’ पहले से ही आंखों से आंखों का संपर्क करने और भावनात्मक स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने में बेहतर है। वह आसपास का माहौल भी समझता है। चंद और कदमों के बाद वह जीवनभर आपकी देखभाल करने वाला ‘सोतेला बेटा’ बन सकता है। ऐसा किन्तनी जल्दी होगा, उसके को-फाउंडर्स बता सकते हैं। महज 10 साल पहले ही क्या हमने कभी सोचा था कि 25 हजार रुपए की ‘रूम्बा’ मशीन हमारे घरों में झाड़ू-पोंछा करने वाली मेड की जगह ले लेगी? आज रूम्बा आधुनिक शहरी घरों, यहां तक कि मध्यमवर्गीय परिवारों में भी मौजूद है। मेड अब कुक बन कर ज्यादा कमाई कर रही हैं और मशीनें दिन के किसी भी समय बिना शिकायत अपना काम कर रही हैं। फंडा यह है कि आधुनिक मशीनें इसानों द्वारा निमित्त खालीपन को भरने में पर्याप्त समझदार हो रही हैं। लेकिन क्या वे हमारी भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा कर पाएंगी? जवाब सिर्फ समय ही देगा। एन. रघुरामन

भारतीय के बजाय विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट क्यों?

एआई के लिए सेमीकंडक्टर बनाने वाली एनवीडिया कंपनी की वैल्यू भारत की जीडीपी से ज्यादा

विदेशी क्लाउड कम्पनियों को साल 2047 तक इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। इस टैक्स छूट की

में ऑफिस स्थापित करने की बाध्यता नहीं है, इससे भारत के श्रम कानून उन पर लागू नहीं

सबसे गर्म 100 शहरों वाले भारत में नदियां और तालाब पहले ही सूख रहे हैं। गर्मी से



है। इलॉन मस्क अपनी स्पेस एक्स कंपनी के शेयरों के दम पर 174 देशों से भी अधिक सम्पत्ति वाले दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। डेटा, तेल और एआई- इन तीन बड़ी बातों से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की बादशाहत को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 5 सालों में 500 अरब डॉलर यानी 47 लाख करोड़ रुपए की अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए भारत पर दबाव बढ़ रहा है। उसी कड़ी में भारत में डेटा सेंटरों की स्थापना हो रही है, क्योंकि अमेरिकी डेटा सेंटरों के लिए मशीनों और सेवाओं का भारत में आयात होगा। इस परिदृश्य के पांच पहलुओं को समझना जरूरी है : 1. अमेरिकी एआई कंपनियों को सफल होने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर की जरूरत है। हमारे आम बजट में सिर्फ 1 साल के लिए टैक्स के नियम बनाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका के दबाव में इस साल के बजट में

वजह से अगले चार सालों में 5000 मेगावाॉट यानी पांच गीगावाॉट के विदेशी डेटा सेंटरों स्थापित करने का लक्ष्य है। स्वदेशी कंपनियों को टैक्स छूट नहीं मिलना संविधान की समानता के उल्लंघन के साथ सार्वभौमिकता का भी हनन है। 2. दुनिया के कुल डेटा का लगभग 25फीसदी भारत से जनरेट हो रहा है। भारत में डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं होने से अमेरिका की टेक कंपनियां और मालिक मालामाल हो रहे हैं। पिछले साल यूपीआई से 314 लाख करोड़ के लेनदेन हुए, जो ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट का 49फीसदी है। रिजर्व बैंक ने 2018 में डेटा को भारत में सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाए थे, जिन्हें विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं किया जा रहा है। 3. केंद्र सरकार ने पिछले साल कहा था कि विदेशी कंपनियों को भारत में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करने के बाद ही टैक्स में छूट मिलेगी। अब उन्हें भारत

होंगे। विदेशी डेटा सेंटर कंपनियों को राज्यों की सरकारें जमीनों का आवंटन और रियायतें दे रही हैं। खरबों डॉलर के निवेश वाले इन डेटा सेंटरों से औद्योगिक क्रांति नहीं होने से दीर्घकालिक रोजगारों का सृजन भी नहीं होगा। 4. डेटा सेंटरों को चीबीसों घंटे बिजली चाहिए या डीजल वाले जनरेटर सेट के बैंकअप की जरूरत होगी। चार सालों में डेटा सेंटरों में बिजली की खपत 6 गुना बढ़ जाएगी। इनकी सहूलियत के लिए भारत में परमाणु बिजली का कानून नया बनाया गया है।

इनसे चेन्नॉबिल जैसे हादसे होने का खतरा बढ़ गया है। राज्यों की बिजली कंपनियां सात लाख करोड़ के कर्ज से दबी हैं। डेटा सेंटरों की वजह में ऊर्जा के साथ विदेशी मुद्रा का संकट गहरा सकता है।

5. गर्मी के उत्सर्जन और रैंडिएशन की वजह से अमेरिका में डेटा सेंटर बंद करने का आंदोलन चल रहा है। दुनिया के

भारत की जीडीपी को 4.5 फीसदी का झटका लग सकता है। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग जल संकट से ग्रस्त हैं। खरबों गैलन पानी निगलने वाले डेटा सेंटरों की वजह से भूगर्भजल के साथ पेयजल का संकट गहरा सकता है। अंतरिक्ष और समुद्र में डेटा सेंटर के खाम बेचकर मस्क टेक-कुबेर बन गए हैं। गरीबी, एकाधिकार, बेरोजगारी, जलवायु जोखिम और साम्राज्यवाद बढ़ाने वाले विदेशी डेटा सेंटरों की टैक्स छूट खत्म हो। संविधान के अनुसार डेटा सेंटरों में पर्यावरण संरक्षण और श्रम कानूनों को लागू करने की जरूरत है। हमारे खाब बजट में सिर्फ 1 साल के लिए टैक्स के नियम बनाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका के दबाव से इस साल के बजट में विदेशी क्लाउड कम्पनियों को साल 2047 तक इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। इसका क्या कारण है? (ये लेखक के अपने विचार हैं, विराम गुप्ता)



के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटाना। दूसरी, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए विपक्ष के उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करना। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पांच राष्ट्रीय और 21 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को दानदाताओं से आधिकारिक रूप से कुल 7,445 करोड़ रुपए मिले थे। यह चुनावी फंडिंग का वैध हिस्सा है। व्यावसायिक कंपनियों और व्यक्तियों के लिए दलों को डोनेट करने की अनुमति देने वाली विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को फरवरी 2024 में उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। लेकिन अधिकांश दलों ने इसका विकल्प तलाशने के तरीके विकसित कर लिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भी आंतरिक रूप से विभाजित तृणमूल कांग्रेस के बैंक खाते में 630 करोड़ से अधिक की राशि शेष होना यह दर्शाता

केवल एक छोटा हिस्सा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) ने अनुमान लगाया है कि चुनाव की कुल लागत 1.35 लाख करोड़ रु. रही थी। यह 2004 के लोकसभा चुनाव में खर्च हुए 15,000 करोड़ की तुलना में 900फीसदी अधिक है। यह 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर हुए 1.2 लाख करोड़ रु. के खर्च से भी अधिक है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय की है। प्रत्येक सांसद कानूनी रूप से अधिकतम 95 लाख तक खर्च कर सकता है, जबकि विधायकों के लिए यह सीमा 28 लाख से 40 लाख के बीच है। लेकिन दलों के चुनावी खर्च पर सीमा नहीं है। इन अनुमानों के आधार पर, 2024 के लोकसभा चुनाव में अवैध फंडिंग 1 लाख करोड़ रुपए से कहीं अधिक रही। यह धन कंपनियों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और अन्य स्रोतों से आया। ये जिन दलों को धन देते हैं, उनसे

सभा के उम्मीदवारों के चुनाव अभियानों में बड़ी मात्रा में धन लगाती हैं। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी (एआईपीएसी) जैसे प्रभावशाली फंडिंग ग्रुप्स किसी उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को बना या बिगाड़ सकते हैं। एआईपीएसी दशकों से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे नेताओं को वित्तीय समर्थन देता रहा है।

अंतर केवल पारदर्शिता का है। हालांकि, अमेरिकी व्यवस्था में भी कार्टेल और विशेष हित समूहों का अवैध धन नकद के रूप में उम्मीदवारों तक पहुंचता है। भारत में चुनावों में नकद फंडिंग का अनुप्रात कहीं अधिक है और यह व्यापक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यद्यपि केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार यूपीए के फोन-बैंकिंग वाले दौर की तुलना में कम हुआ है, लेकिन राज्य और नगर निकाय स्तर पर भ्रष्टाचार

सुजन के लिए बहुत कम किया है। ये दोनों वर्ग मुख्यतः सांशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों पर ही अधिक मुखर हैं। अधिकांश भारतीय इस बढ़ते असंतोष से अप्रभावित हैं। लेकिन सरकार उन्हें हल्के में नहीं ले सकती। राम मंदिर की दानपेटी की चोरी की घटना एक चेतावनी है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता तक पहुंची थी।

यदि भ्रष्टाचार का दाग भगवान के घर तक पहुंचता दिखाई देता है, तो भाजपा के किले की नींव कमजोर पड़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी अनेक संकटों का सामना कर चुके हैं- कोविड, टैरिफ, युद्ध आदि। लेकिन भ्रष्टाचार अनेक सिरों वाले राक्षस की तरह है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले उस पर नियंत्रण पाना मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। (ये लेखक के अपने विचार हैं,मिन्हाज मर्चेंट)

यूक्रेन के हमले से रूस में भी होर्मुज जैसा संकट, जहाजों की आवाजाही रुकी, 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले हुए
मॉस्को। रूस में गेहूँ की कीमतें बढ़ने लगीं- रिपोर्ट्स के



मुताबिक रूस वेड करीब 25फीसदी गेहूँ का निर्यात एजोव सागर के रास्ते होता है। अगर यह संकट जारी रहा तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूँ निर्यातक है और वैश्विक गेहूँ निर्यात का लगभग 20फीसदी हिस्सा अकेले रूस से आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के करीब 25फीसदी गेहूँ का निर्यात एजोव सागर के रास्ते होता है। अगर यह संकट जारी रहा तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है।एजोव सागर में संकट बढ़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूँ के

अपने गेहूँ का निर्यात ब्लैक सी के दूसरे बंदरगाहों से कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि निर्यात के सबसे व्यस्त मौसम में दूसरे बंदरगाहों की क्षमता इतनी नहीं है कि वे पूरा भार संभाल सकें।

रूस के लिए एजोव सागर इतना खास क्यों है- एजोव सी यूक्रेन और रूस के बीच स्थित एक अंदरूनी समुद्र है, जो केरॉ स्ट्रेट के जरिए ब्लैक सी से जुड़ा है। 2003 में यूक्रेन और रूस ने इस समुद्री क्षेत्र को साझा इस्तेमाल करने का समझौता किया था। लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने इस समझौते का कई बार

बाद रूस ने एजोव सागर के आसपास के लगभग पूरे यूक्रेनी तट पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे रूस का समंदर तक बता दिया था। आकार में छोटा होने के बावजूद, एजोव सागर रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है।

सोवियत काल में विकसित हुए नदियों और नहरों का विशाल नेटवर्क इसी समुद्री मार्ग से जुड़ता है।

इसके जरिए दक्षिणी रूस से तेल, गेहूँ, सूरजमुखी का तेल, इस्पात और अन्य सामान पहले ब्लैक सी और फिर दुनिया के कई देशों तक पहुंचाया जाता है।

वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- हर जान कीमती हैं, केंद्र-दिल्ली सरकार को आदेश- रोजाना मेडिकल जांच हो

नयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक

उनका वजन 8.9किग्रा तक गिर गया है। सीजेपी का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग-

अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत और



की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है। उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नीट पेपर लोक के विरोध में 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक भी उनके आंदोलन में शामिल

वांगचुक 19 दिन से भूख हड़ताल पर

और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। याचिका में जबर्न खाना देने के निर्देश देने की मांग भी की गई थी।केंद्र की ओर से सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी डॉक्टर वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वांगचुक नीट पेपर लोक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं।

सीबीआई का दावा-लातूर कोचिंग संचालक ने नीट का पेपर खरीदा, केमिस्ट्री के 132 प्रश्न मिले, 111 असली पेपर से मैच

लातूर। सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 पेपर लोक मामले में बुधवार को स्पेशल कोर्ट में बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, महाराष्ट्र के लातूर की कोचिंग सेंटर संचालक शिवराज रघुनाथ मोटोगांवकर ने एनटीए के पेपर सेट पर से केमिस्ट्री के प्रश्न हसिल करने के लिए रु5 लाख दिए थे। आरोपी मोटोगांवकर के मोबाइल से मिले हस्तलिखित नोट्स में 132 प्रश्न मिले, जिनमें से 111 प्रश्न एनटीए के मास्टर प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं। मोटोगांवकर का बेटा कुलकर्णी की कोचिंग क्लास भी जाता था। नीट-यूजी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर हुई थी। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और

री-एजान का फैसला लिया गया। सीबीआई ने मोटोगांवकर का फोन बरामद किया-सीबीआई ने मोटोगांवकर का फोन बरामद किया



है, जिसमें रसायन केमिस्ट्री के 132 प्रश्न से लिखे प्रश्नों वाली 36 तस्वीरें (पांच डुप्लिकेट तस्वीरें) मिली हैं। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि इनमें से 111 प्रश्न नीट (यूजी) 2026 के लिए तैयार किए गए एनटीए के मास्टर प्रश्न सेट से मेल खाते हैं। एजेंसी ने कहा कि मोटोगांवकर ने कुलकर्णी की केमिस्ट्री लैबटोरियल क्लासेस में दिए गए पेपर से हैंड रिटन नोट्स तैयार

90 लोग घायल हुए। सरकार ने हिंसा भड़काने का आरोप वांगचुक पर लगाया। इसके दो दिन बाद, 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेज दिया गया। इरोम ने 16 साल तक अनशन किया, जानें ऐसी ही 5 हड़तालें-देश में पहले भी कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लंबी भूख हड़ताल कर चुके हैं। महात्मा गांधी से लेकर जी.डी. अग्रवाल तक कई लोगों ने अनशन का सहारा लिया। सबसे लंबी भूख हड़ताल का रिकॉर्ड इरोम शर्मिला के नाम है। इरोम शर्मिला ने मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफ्सा) हटाने की मांग को लेकर करीब 16 साल (2000-2016) तक भूख हड़ताल की थी। इस दौरान उन्हें जीवित रखने के लिए नाक के जरिए तरल आहार (फॉर्स-फीडिंग) दिया जाता था।

सीजेपी चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के बाद बनी थी। सीजेपी ने आरोप लगाया कि छात्रों के लिए आवाज उठाने वाले वांगचुक को सरकार की ओर से सिर्फ खामोशी मिली है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार जवाबदेही से बच रही है और उसका रवैया क्रूर है। लद्दाख को राज्य बनाने की मांग, वांगचुक 170 दिन जेल में रहे-वांगचुक इससे पहले लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 170 दिन तक जोधपुर जेल में रहे। उन पर आरोप था कि

किए थे। सीबीआई ने मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, बिहार पुलिस ने मामले में अलग से 30 लोगों को गिरफ्तार किया था।शिवराज पहले पार्ट-टाइम टीचर था, आज रु1500 करोड़ की संपत्ति-कोचिंग संचालक मोटोगांवकर का महाराष्ट्र के लातूर में रेनुकाई करियर सेंटर (आरसीसी) है। पहले यह मामूली पार्ट-टाइम टीचर था। आज नेटवर्क रु1500 करोड़ बताई जा रही है। सीबीआई का आरोप है कि मोटोगांवकर की पेपर लोक नेटवर्क से पुरानी साठगांठ रही है। भास्कर ने इस कोचिंग में पढ़ने वाले नीट 2025 में सफल छात्रों की पड़ताल की। इसमें 19 छात्रों का एम्स में सिलेक्शन हुआ था।12 छात्रों का एम्स दिल्ली, 5 का हैदराबाद और 3-3 का भोपाल व वाराणसी एम्स में सिलेक्शन हुआ।

शेख हसीना की फांसी लगभग तय हैं फिर भी बांग्लादेश क्यों जाना चाहती हैं- क्या भारत का रुख बदल गया

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। अगस्त 2024 में तख्तापलट के बाद वो भागकर

गिरफ्तारी पर किसी बड़े विरोध प्रदर्शन की भी उम्मीद कम है। पुलिस इसे कुचल सकती है। बांग्लादेश के पीएम तारिक

ताकत से खड़े होने का मौका है और सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। अल-जजीरा के मुताबिक, हसीना



भारत आ गई थीं। उन्हें बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में मौत की सजा सुनाई है। बांग्लादेशी नेता कह रहे- वापस आने पर इस सजा को अंजाम दिया जाएगा। सवाल-1: शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की बात कहां से उठी? जवाब: ये चर्चा शेख हसीना के ही बयानों से शुरू हुई। उन्होंने 29 जून को एक टीवी चैनल से ई-मेल इंटरव्यू में कहा-‘मुझे मौत का डर नहीं है। मैंने 1975 में अपना पूरा परिवार खो दिया था। 21 अगस्त को ग्रेनेड से मेरी हत्या की कोशिश हुई। मैं हर साजिश से लड़ते हुए बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़ी रही और वोट से 5 बार पीएम चुनी गई। मेरी पूरी जिंदगी बांग्लादेश की जनता, अगामी लीग (हसीना की पार्टी) और बांग्लादेश के हित से जुड़ी रही है। मैं हर रुकावट, हर साजिश को पार करते हुए इस साल अपने मुल्क लौटूंगी।’ इसके बाद 10 जुलाई की सुबह हसीना ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को भी टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताया कि दिसंबर 2026 तक भारत से बांग्लादेश लौटेंगी और अपनी पार्टी के कुछ और निर्वासित नेताओं के साथ सरेंडर करेंगी। शेख हसीना ने कहा, ‘हो सकता है कि लौटने पर वे मुझे गिरफ्तार कर लें, वे मुझे मार भी सकते हैं। फिर भी, मुझे जाना ही होगा। मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भयानक तरह से दमन हो रहा है।’ हसीना की सरकार में गृहमंत्री रहे असदुज्जमान खान भी निर्वासित हैं, उनको भी मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा, ‘हम सब मिलकर अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे।’ सवाल-2: बांग्लादेश लौटने पर उनके साथ क्या-क्या हो सकता है? जवाब: शेख हसीना पर उनके खिलाफ आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स की हत्याओं के लिए पुलिस और सेना

रहमान के स्टूटैजिक एडवाइजर जाहिद-उर-रहमान ने कहा है, ‘देश की जनता चाहती है कि उनके जर्म के लिए उन्हें मौत की सजा दी जाए। अगर वो वापस आईं, तो इस सजा को अंजाम

विदेश से ही पार्टी को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। वो 100 से ज्यादा संसदीय इलाकों में अपनी पार्टी के लोगों के साथ ऑनलाइन बैठकें कर रही हैं। इंटरव्यू में

बधाई को हाईलाइट किया और अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताई। अगले ही दिन बीएनपी के सीनियर नेता सलाहुद्दीन अहमद ने भारत से शेख हसीना का प्रत्यर्पण करने की पार्टी की मांग



5 अगस्त 2024 को हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना हेलिकॉप्टर से दिल्ली आ गई थीं।

दिया जाएगा। जनता यही चाहती है। उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे वकील लाने दो।’ सवाल-3: जब फांसी की सजा हो चुकी, तो फिर लौटने का दांव क्यों खेल रही हसीना? जवाब: इसकी 2 बड़ी वजहें हैं- बांग्लादेश की राजनीति में वापसी की कोशिश-प्रतिबंध के बावजूद अगामी लीग एक्टिव हो रही है। कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। 23 जून को पार्टी ने 77वां स्थापना दिवस मनाया, तो दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बीते हफ्ते शेख हसीना के खिलाफ हुई एक रैली के दौरान बम धमाका हुआ। इसमें 3 लोग घायल हुए, जबकि मंच पर शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट मूवमेंट

हसीना ने कहा, ‘अगामी लीग पर कई हमले हुए, बैंन लगाया गया, लेकिन जनता की ताकत से पार्टी दोबारा उठ खड़ी हुई। ऐसी कोशिशों में वो पहले भी फेल हुए हैं, दोबारा होंगे। बैंन लगाकर पार्टी के ऑफिस और पॉलिटेक्निक एक्टिविटी बंद कर सकते हैं, लेकिन पार्टी वर्कर्स जुलूस निकाल रहे हैं। आम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये संकेत है कि अगामी लीग फिर से मजबूत होने लगी है।’ इसके अलावा हसीना के बेटे सजीब वाजेद जाँय फिलहाल अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के मुद्दों पर एक्टिव हैं। अगर हसीना उनके लिए राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहे, तो

दोहराई। तारिक ने भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जाएगी। सवाल-4: तो क्या भारत दबाव में हसीना को वापस भेज देगा? जवाब: दिसंबर 2024 से अब तक बांग्लादेश कई बार भारत को हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध भेज चुका है। 14 जुलाई को भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है- पूर्व पीएम (शेख हसीना) के मामले में हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रत्यर्पण का मामला कानूनी मुद्दा है, उसी तरीके से निपटा जाएगा। इस बयान और भारत के रुख का मतलब समझिए- दरअसल, 2013 में हसीना के पीएम रहते भारत-बांग्लादेश में

का कोई रास्ता है? जवाब: बांग्लादेश में मौत की सजा से बचने के लिए हसीना के पास 2 रास्ते हैं- ट्रिब्यूनल में ही सजा को चुनौती दे और केस जीत जाए- ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हसीना वहीं अपील कर सकती है। हालांकि अपील की समयसीमा 30 दिन की है, लेकिन मार्च 2026 में हसीना के वकील ट्रिब्यूनल को पत्र भेजकर सजा को अवैध बताकर इसे रद्द करने की मांग कर चुके हैं।

धूमन राइट्स वाच और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी बिना सुनवाई के हुई इस सजा पर चिंता जता चुके हैं। इसलिए हो सकता है, हसीना को ट्रिब्यूनल सुनवाई में शामिल होने का मौका दे दे। हालांकि ट्रिब्यूनल से हसीना आरोपों से बरी हो जाएं, ये मुश्किल है। सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करके स्टैंड ले- हसीना सरेंडर से पहले ही इस फैसले के खिलाफ बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर सुनवाई शुरू कर सकता है या फिर स्टैंड दे सकता है। हालांकि बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट पर सत्ता का प्रभाव रहता है। मसलन-दिसंबर 2014 में हसीना की सरकार के दौरान बांग्लादेश की पार्टी जमात-ए-इस्लामी के नेता अजहरुल इस्लाम को 1971 में नरसंहार, मर्डर, रेप जैसे मामलों में ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा दी। अजहरुल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उसने सजा बरकरार रखी। फिर हसीना के तख्तापलट के बाद मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इसी तरह हसीना की सरकार ने 2013 में जमात को बैन किया था। हसीना के हटने के बाद यूसुफ सरकार ने जमात पर से बैंन हटा दिया। 2013 से 2016 के बीच हसीना के दौर में भी अब्दुल कादर मोल्ला, मोतीउर रहमान निजामी जैसे 5 जमात नेताओं और बीएनपी वेंस सलाउद्दीन कादर चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अपील खारिज कर दी गई और इन सभी को फांसी हो गई।



को आदेश देने का आरोप है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल ब्रगडम्स ट्रिब्यूनल, यानी आईसीटी-बीडी नवंबर में शेख हसीना को मौत की सजा सुना चुकी है। ये पहली बार है, जब बांग्लादेश में किसी पूर्व पीएम को मौत की सजा सुनाई गई है। अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाकर सरेंडर करती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करके फांसी देने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील भी की जा सकती है। हसीना की पार्टी अगामी लीग पर बांग्लादेश में बैंन है। इसलिए

के प्रमुख चेहरे नाहिद इस्लाम समेत नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के कई नेता मौजूद थे। अगामी लीग के नेता कह रहे हैं कि उसका दौर इस सरकार से कहीं बेहतर था। 2009 से 2024 तक हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश कपड़े के एक्सपोर्ट में बांग्लादेश दुनिया का बड़ा सेंटर बना, लाखों लोग गरीबी से बाहर आए। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्टूटैजिक स्टडीज प्रोग्राम वेंड डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र कहते हैं कि अब शेख हसीना को लगने लगा है कि दोबारा बांग्लादेश में

भी ये बिना बांग्लादेश लौटे मुमकिन नहीं है। भारत में अब ज्यादा दिन रहना मुश्किल-विवेक मिश्र कहते हैं, ‘आखिर कब तक हसीना भारत में या किसी और देश में रहेगी? भारत भले ये बात न कहे, लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जैसा है। एक निर्वासित नेता को रखना आसान नहीं होता। शेख हसीना के साथ अमेरिका का भी सपोर्ट नहीं है। बांग्लादेश और चीन बहुत नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में भारत तारिक रहमान के दौर में बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते चाहता है।’ इसके संकेत भी मिलने लगे

प्रत्यर्पण संधि हुई। खास तौर पर सीमाई इलाकों में घुसपैठियों और अपराधियों के प्रत्यर्पण को लेकर। संधि के मुताबिक, अगर किसी देश में मौजूद दूसरे देश के अपराधी को एक साल या उससे ज्यादा कैद की सजा मिले और अपराध ऐसा हो, जिसमें दोनों देशों में सजा होती हो, तो प्रत्यर्पण हो सकता है। 2016 में संशोधन के तहत अपराध का सबूत देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने यहां की कोर्ट से जारी वारंट देना काफी है।हालांकि संधि में 3 आर्टिकल हैं, जिनके जरिए भारत शेख

